

यह तारीख भारत में आईएफ तकनीक के लिहाज से खास है। इस तकनीक का फल टेस्ट ट्रॉब बैरी के जनक डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय है। डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म 16 जनवरी 1931 को हुआ था। कालकाता के डॉ. सुभाष मुखोपाध्याय ने भारत में पहली बार 25 जुलाई, 1978 को टेस्ट ट्रॉब बैरी का सफल परीक्षण किया। तीन अक्टूबर, 1978 को इस टेस्ट ट्रॉब बैरी का जन्म हुआ।



# उज्ज्वल दुनिया

रांची, दिल्ली और यूपी से एक साथ प्रकाशित



वर्ष, 09

पृष्ठ 12

अंक 346

रांची, बुधवार, 19 जून 2024

मूल्य 3 रुपये

RNI No.- JAHIN/ 2014/59794

ujjwalduniyapress@gmail.com

## हजारीबाग सरफा

सोना (बिकी) ₹ 6,780.00 प्रति ग्राम

चांदी ₹ 95.00 प्रति ग्राम

पहले थोरूम के रूप में

स्थापित हजारीबाग शहर का गोरा

देश हित के लिए मतदान अद्यता करें।

4 दशकों से निरंतर सेवा में

अनूठे विश्वास और आईने की सच्चाई के साथ

DIAMOND, GOLD, SILVER 100% शुद्धता के साथ

Certified Jeweller श्री अलंकार ज्वेलर्स श्री अलंकार ज्वेलर्स

A House of Traditional Trust

SRI ALANKAR JEWELLERS

MALVIYA MARG, HAZARIBAG, Mob. : 9934943065

## सप्तगिरि आई.टी.आई.

भारत सरकार N.C.V.T नई दिली से मान्यता प्राप्त

ट्रेड- मैकेनिकल डीजल, फिटर, इलेक्ट्रीशियन

• Wi-Fi Campus नामांकन प्राप्त य सत्र- 2024-26

• CCTV Camera Hostel Facility Available

• Campus Selection

• Scholarship Facility

सिन्दूर, महेन्द्र कॉलेजी, हजारीबाग

9470333159

9608881460

Email: saptaginiit@gmail.com

## धर्मस्थल लुगुबुरु-मरांगबुरु को बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में जल्द से जल्द करें विकसित : चम्पाई सोरेन

मुख्यमंत्री ने पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा की



रांची, उज्ज्वल दुनिया सं

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग के अध्यक्ष के बीच बैठक की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फटाड़ी मंदिर परिसर संगीकारी को इस बैठक में प्राकृतिक सौन्दर्यता बेमिसाल है। यहाँ विभिन्न समुदायों के कई अहम धार्मिक स्थल तथा अलग-अलग कला-संस्कृति का एक अनोखा मिशन है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदिवासी धर्मवर्लाभियों के आस्था एवं विश्वास का धर्मस्थल लुगुबुरु

## मां गंगा ने मुझे गोद लिया, तीसरी बार चुना जाना ऐतिहासिक: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, उज्ज्वल दुनिया सं पीएन किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की

30 हजार से अधिक कृषि संख्या नहिलाओं को प्रगति प्रदान किए



वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नन्दन मोदी मंगलवार को काशी पहुंचे। उन्होंने देशभर के किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान सभा को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वहली बार मैं काशी आया हूं। बाबा विश्वासाथ, मां गंगा और काशी जीतने के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। काशी की जीतना ने मुझे जिताकर धन्य कर दिया। ऐसा लम्भा है कि अब तो माता पंथ ने भी मुझे गोद ले लिया और मैं वहीं का हो गया हूं। मैं आपका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि इस बार देश के चुनावों ने जय इतिहास रच दिया है। दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार को लगातार तीसरी बार चुना गया हो। भारत की जीतना ने यह कर दिखाया है। उन्होंने देशसभियों को विश्वास दिलाया कि वे दिन-रात ऐसे ही महनत करेंगे और लोगों के सपनों और संकल्पों को पूछ करेंगे के लिए हार्दिक करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर देश के चुनावों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की 17वीं किस्त जारी की।

## ACHIEVERS' CLASSES

"Come with Dreams, Leave with Success"

A Premier Coaching Institute for VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Pass (DROPPER), NTSE, OLYMPIAD, IIT-JEE (MAIN + ADV.), & NEET EXAMS

OUR PREVIOUS YEARS NEET TOPPERS

**Congratulations to our JEE-MAIN 2024 TOPPERS....**

TOTAL SELECTION FOR JEE- ADVANCED 223 STUDENTS

SAHIL	PRAKHAR	ASHISH	ADITYA	AVYUSH	SIKANDAR	SREYAS	SOURYA	PRAKHAR	And many more....
99.86 Percentile	99.82 Percentile	99.73 Percentile	99.61 Percentile	99.24 Percentile	99.14 Percentile	99.1 Percentile	99.05 Percentile	99.05 Percentile	

SELECTION IN 2023

SELECTION IN JEE-ADVANCED 42

SELECTION IN JEE-MAIN 220

SELECTION IN NEET 50

**Admission is going on....**

Schooling Facility Is Available For 10th Pass Students

Main Branch: ABOVE BANK OF BARODA, KALIBARI ROAD, HAZARIBAG, Contt. - 9006618149, 9955455935, 9534188949, www.achieversclasses.com

हम सब का संकल्प हो  
झारखण्ड नथा मुक्त हो



श्री चम्पाई सोरेन  
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

# हमाया उद्देश्य नथा नुक्क

हो झारखण्ड प्रदेश

विशेष नथा मुक्त अभियान  
12 जून से 26 जून

आम जनता के सहयोग से नथा मुक्त समाज का होगा निर्माण

नथा से छुटकारे के लिए तुरंत संपर्क करें:-

इनपास, राँची

केंद्रीय मनोचिकित्सा  
संस्थान, राँची

अखिल भारतीय  
आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर

जिला अस्पताल के  
आईसीटीसी/एआटीसी परामर्श केंद्र

टेल फ्री नं.  
**112**  
(24x7)  
पर कॉल करें















# संपादकीय

# भारत में लैंगिक असमानता की बढ़ती खार्ड

विश्व आर्थिक मर्च द्वारा हाल म प्रस्तुत किये गए लागतक अंतर के आंकड़ोंने एक ज्वलतं प्रश्न खड़ा किया है कि शिक्षा, आय, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आधी दुनिया को उसका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? निस्संदेह, हमारे सत्ताधीशों को सोचना चाहिए कि लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर क्यों है? लगातार महिलाओं की दोयम दर्जा की स्थिति का बना रहना नीति-नियंताओं के लिये आत्मसंथन का मौका है। निश्चय ही यह रिप्टिटि भारत की तरक्की के दावों से मेल नहीं खाती। इसके बावजूद उम्मीद जगाने वाला तथ्य है कि पिछले वर्ष जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं की एक तिहाई हिस्सेदारी को लेकर विधेयक पारित हो चुका है। इसके बावजूद हाल में सामने आए आंकड़े परेशान करने वाले हैं और तरक्की के दावों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। यह विचारणीय प्रश्न है कि सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाने और कायदे कानूनों में बदलाव के बावजूद लैंगिक असमानता की खाई गहरी क्यों होती जा रही है? ये रिप्टिटियां समाज में इस मुदे पर खुले विवरणों की जरूरत को बताती हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में सीमित मात्रा में महिलाओं के संसद में पहुंचने ने भी कई सवालों को जन्म दिया है। निश्चित रूप से तमाप सरकारी घोषणाओं के बावजूद जमीन पर महिला असमानता के दंश विद्यमान रहना बड़ी चुनौती है।

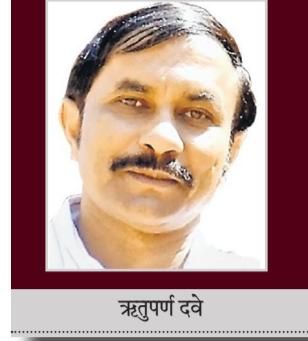
लैंगिक अंतर सूचकांक में पिछले साल भारत 127वें स्थान पर था, जो 2022 में 135वें स्थान से 1.4 प्रतिशत अंक और आठ पायदान ऊपर था। लेकिन इस वर्ष फिर दो पायदान ऊपर चढ़ा है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को 99वें, चीन को 106वें, नेपाल को 117वें, श्रीलंका को 122वें, भूटान को 124वें और पाकिस्तान को 145वें स्थान पर रखा गया है। आईसलैंड (93.5 फीसदी) फिर से पहले स्थान पर है और डेढ़ दशक से सूचकांक में सबसे अगे है। शीर्ष 10 में शेष नौ अर्थव्यवस्थाओं में से आठ ने अपने अंतर का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा पाट लिया है। निश्चित तौर पर किसी भी समाज में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में लंबा समय लगता है, लेकिन इस दिशा में सत्ताधीशों की तरफ से ईमानदार पहल होनी चाहिए। यह भी एक हकीकत है कि दुनिया के सबसे ज्यादा आजादी वाले देश के आंकड़ों की तुलना दक्षिण एशिया के छोटे देशों से नहीं की जा सकती। इसमें दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में सरकारों द्वारा लैंगिक समानता के लिये नीतियां बनाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं। जिसकी एक वजह समाज में पुरुष प्रधानता की सोच भी है। जिसके चलते यह आभास होता है कि आधी दुनिया के कल्याण के लिये बरी योजनाएं महज योषणाओं तथा फाइलों तक सिमट कर रह जाती हैं। भारत में महिलाओं की उपेक्षा, भेदभाव, अत्याचार एवं असमानता की स्थितियों का बना रहना विडम्बनापूर्ण हैं। भारत में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के स्वरूप तो बहुत सुनें को मिलते हैं, महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार भी पुरुषों के बराबर दिया गया है, परन्तु यदि वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक एवं विसंगतपूर्ण है। हमारे सत्ताधीशों के लिये यह तथ्य विचारणीय है कि हमारे समाज में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ रही है? हम समान कार्य के बदले महिलाओं को समान वेतन दे पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जाहिर है यह अंतर तभी खत्म होगा जब समाज में महिलाओं से भेदभाव की सोच पर विराम लगेगा। यह संतोषजनक है कि माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में लैंगिक समानता की स्थिति सुधीरी है। फिर भी महिला सशक्तीकरण की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देर-सेरे महिला आरक्षण कानून का ईमानदार क्रियान्वयन समाज में बदलावकारी भूमिका निभा सकता है। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक नेतृत्व इस मुद्दे को अपेक्षित गंभीरता के साथ देखे।

माहात्मा गांधी का समर्पण करते हुए है। वह न केवल वस्त्र का जन्म दिया है बल्कि उनका मरण-पोषण और उन्हें संस्कार भी देती है। महिलाएं अपने जीवन में एक साथ कई भूमिकाएं जैसे- मां, पती, बहन, शिक्षक, दोस्त बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाती हैं। बाबूजुद क्या कारण है कि आज भी महिला असमानता की स्थितियां बना हुई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए भारत सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे। सरकार को अपनी लैंगिकवादी सोच को छोड़ना पड़ेगा। वर्तीयक भारत सरकार के खुद के कर्मचारियों में केवल 11 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये अधिक एवं नये अवसर सामने आने जरूरी है। भारत में महिला रोजगार को लेकर चिंताजनक स्थितियां हैं। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकार्नमी (सीएमआई) नाम के थिंक टैक ने बताया है कि भारत में केवल 7 प्रतिशत शहरी महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पास रोजगार है या वे उसकी तलाश कर रही हैं। सीएमआई के मुताबिक, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में हमारा देश इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी पीछे है। रोजगार या नौकरी का जो क्षेत्र स्त्रियों के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जरिया रहा है, उसमें इनकी भागीदारी का अनुपात बेहद चिंताजनक हालात में पहुँच चुका है। यों जब भी किसी देश या समाज में अचानक या सुनियोजित उथल-पुथल होती है, कोई आपदा, युद्ध एवं राजनीतिक या मनुष्यजनित समस्या खड़ी होती है तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर स्त्रियों पर पड़ता है और उन्हें ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है।

दावोंस में हुए बल्कि इकनॉमिक फोरम में ऑफसकैम ने अपनी एक रिपोर्ट हाईटाइम टू केयरल में घरेलू औरतों की आर्थिक स्थितियों का खुलासा करते हुए दुनिया को चौका दिया था। वे महिलाएं जो अपने घर को संभालती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं, वह सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अनगिनत सबसे मुश्किल कामों को करती है। अगर हम यह कहें कि घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा पेशा है, जिसमें 24 घंटे, सातों दिन आप काम पर रहते हैं, हर रोज क्राइसिस झेलते हैं, हर डेलाइन को पूरा करते हैं और वह भी बिना छूटी के। सोचिए, इतने सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई बेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही उसके इस काम को राष्ट्र की उन्नति में योगधूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। प्रश्न है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के त्रम का आर्थिक मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों?

नरन्द्र मोदी की पहल पर निश्चित ही महिलाओं पर लगा दोषम दर्जा का लेबल हट रहा है। हिंसा एवं अत्याचार की घटनाओं में भी कमी आ रही है। बड़ी संख्या में छोटे शहरों और गांवों की लड़कियां पढ़-लिखकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे उन क्षेत्रों में जा रही हैं, जहां उनके जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। वे टैक्सी, बस, ट्रक से लेकर जेट तक चला-उड़ा रही हैं। सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रही है। अपने दम पर व्यवसायी बन रही हैं। होटलों की मालिक हैं।

# ਮਾਂਗ੍ਰਿਮਾਂਡਲ ਗਠਨ ਨੇ ਤੋਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ



ऋतुपण दव



एक बार म हा 72  
सदस्यीय भारी भरकम  
मंत्रिमंडल की वजह  
लोग कुछ भी बताएं  
लेकिन यह नरेन्द्र  
मोदी की चतुराई कही  
जाएगी जो उन्होंने एक  
बारगी सारे किन्तु-  
परन्तु पर विराम  
लगा एक तीर से कई  
निशाने साथे

नादा नारामंडल का गठन जल्द ही था। लेकिन कायसों का दौर खत्म नहीं हुआ। एक बार में ही 72 सदस्यीय भारी भरकम मंत्रिमंडल की वजह लोग कुछ भी बताएं लेकिन यह नरेन्द्र मोदी की चतुराई कही जाएगी जो उन्होंने एक बारगी सारे किन्तु-परन्तु पर विराम लगा एक तीर से कई निशाने साधे। इससे न केवल सहयोगियों बल्कि भाजपा के आनुषांगिक संगठनों को भी बड़ा संदेश गया कि भले ही सीटें घटीं लेकिन मोदी की हैसियत वही है। घटक दलों के सहयोगियों का मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल बंटवारे में मिले पद और कद से भी काफी भ्रम टूटा। साफ दिखा कि नरेन्द्र मोदी ने जो चाहा वो किया। जिस शांति और धैर्य से घटक दलों के साथ पहली बैठक हुई, प्रमुख दोनों सहयोगी नीतीश बाबू और चंद्रबाबू ने मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े उससे राजनीतिक नज्ब टटोलने वालों की भी धड़कनें असहज हुईं। हमउम्र और राजनीति में मोदी से सीनियर होने के बावजूद नीतीश का उनके पैर छूने के लिए झुकना सबको अब भी हैरान कर रहा है।

यह भ्रम ही साबित हुआ कि जेडीयू को रेल तो टीडीपी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिलना तय है। पुरानी सरकारों में रेल मंत्रालय प्रायः गठबन्धन के सहयोगियों के खाते में रहा। मौजूदा मंत्रिमंडल में 33 नए चेहरे हैं जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पहली बार मंत्री बनने वालों में 7 सहयोगी दलों से हैं। 7 महिलाएं भी मंत्री बनीं जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हैं। एक भी मुस्लिम मंत्रिमंडल में नहीं है।

जादा क बाद पहले भाका ह जब मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। नए मर्टिमंडल स्टेटी, 5 अल्पसंख्यक मरियों को जगह मिली थी। 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मरियों को जगह मिली थी। याकूब अपीलों और जनता से कनेक्ट होने में उन्हरन्द मोदी का कोई सारी नहीं। अब उन्होंने अपील कर विषय को बहस का नया मुद्दा देकर दिया। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से हायमीटी वाले को गुहार लगा दी। भले ही डेस्ट्रेलों नाम बदले लेकिन भारत की तरकीकी की खातिर प्रयास करने वाले एक परिवर्तनीशों के खातिर प्रयास करने वाले एक परिवर्तनी बार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट है। इशारा अबकी बार एनडीए सरकार की आपातकालीन गठबन्धन के सहयोगियों को बता दिया कि अब वो कितने अहम हैं? एससी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के उसके बयान को देखना होगा जिसमें उन्होंने मणिपुर में शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त की थी। यह बयान शायद भाजपा प्रमुख नड्डा के उन्होंने उस बयान का जवाब लगता है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा अब अपने पैरो पर खड़ी है। भागवत के बाद संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार का बयान भी सुर्खियों में रहा जिसमें उन्होंने भी भाजपा की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा। डालांकि इस पर सफाई भी आई। अब सबकी निरागहें लोकसभा अध्यक्ष पर हैं। जिस पर फिर क्यासों का दौर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से वे विविधताओं से भरे भारत देश और उसकी जननीति में मतांतर नए नहीं है। इसीलिए कभी भी नेतृत्व की एनडीए सरकार बेहद मजबूत है तो कभी लगता है कि भाजपा

और उसके अपने महत्वपूर्ण आनुषांगिक दल ही क्यों खफा हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में गजब का प्रदर्शन करते हुए टीडीपी-भाजपा गठबंधन ने बड़े बहुमत वाली जीत हासिल की। दोनों का एजेंडा सबको पता है। टीडीपी मुस्लिम आरक्षण, परिसीमन, सीएए, अमरावती के विकास और विशेष दर्जे पर तबज्जो चाही गी तो कमोवेश जेडीयू भी बिहार में ऐसे ही एंडेंडे के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव में जाएगी। महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव होने हैं। इन हालातों में महत्वपूर्ण घटक कब तक भाजपा के हमराह रहेंगे? जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित बिहार में पद और कद पर कई बातें होनी शुरू हो गई हैं।

# आधुनिक भारत के सच्चे निमाता कौन हैं

Digitized by srujanika@gmail.com

विश्व के सबसे बड़े व प्राचीन प्रजातात्  
भारत में इन दिनों एक बहस की शू  
रुआ हो गयी आधुनिक भारत के  
निर्माता स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्र  
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं या कोई  
और है | आधुनिक भारत के निर्माता का  
सरताज का असली हकदार नेहरू ज  
ना हो कर-सन 2014 के बाद में भारत  
को आजादी मिली व आधुनिक  
भारत का नव निर्माण कार्य शुरू किय  
है सर्व विदित रहे कि स्वतंत्र लोकतंत्र  
की स्वस्थ्य प्रम्पराओं में स्वस्थ्य चच  
होना अच्छी बात है लेकिन बिना सि  
पैर के कहीं कुछ भी चर्चा के नाम बह  
करना है लोकतंत्र के लिए खत्ते व  
घंटी है | भारत को 1947 में आजाद  
नहीं मिली बल्कि 2014 में भाजपा दे  
कुशल नेतृत्व में मिली है | आज ह  
अपने इस आलेख में चिन्तन मनन क  
रहे हैं क्या जो देश सर्वीयों से गुलामी दे  
बेड़ियों म जकड़े था वर्षों रहने के बा

जग जाहिरथा हमारी वास्तविक स्थिति राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रही होगी! आजादी के पूर्व कुछ लोग आज भी साक्षी हैं। अंग्रेजों ने हमें आजादी तो दी, लैकिन देश को चलाने के लिए ना तो कोई संसाधन ना कोई धन का श्रोता हाँ। 1947 में हमारे देश को दो टुकड़े कर अंग्रेजों ने दो भाई में एक दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री व राजनेताओं के समाने देश को सुचारू रूप से चलाने वे भारत की एक नई पहचान अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर्दे असान काम नहीं था ऐसे विषय परिस्थित में मैं यहाँ कुछ घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। बात सन 1950 के दशक के आँखरी साल थे। स्वतंत्र भारत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश की राजधानी नई दिल्ली के मध्य में विदेशी दूतावासों तथा उच्चायोगों के लिए जगह निकाला जाए। आप को स्पष्ट कर दें कि उस समय अमेरिकी, ब्रिटिश, पाकिस्तान और हंगरेदेशों के दतावास बंगलों या छोटी विकास मंत्रालय तथा नई दिल्ली नगर परिषद (ठउठउ) ने नेहरू जी के सपनों को साकार करते हुए जगहों को विकसित किया जिसे चाणक्यपुरी के नाम से लगा थह नाम स्वयं नेहरू जी ने खुद चाणक्यपुरी नाम तय किया था। इसके पीछे प० नेहरू की गहन सोच थी कि कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान थें जिन्होंने अपने ज्ञान का सदुपयोग, जनकल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण चाणक्य के प्रति सारा देश कृतज्ञ रहता है। उन्हें ही कौटिल्य भी कहा गया। आप को स्पष्ट कर दें कि चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक हैं। जो चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार थे। राजधानी के इसी डिप्लोमेटिक एरिया चाणक्यपुरी की एक खास सड़क का नाम पंचशील मार्ग रखा गया है। इसके पीछे तर्क यह थी कि भारत-चीन के बीच रहने वाली तनातीनों के चलते पंचशील शब्द बेमानी हो गया है। लैकिन इन दोनों देशों ने विश्व कट्टनीति को पंचशील का दिल्ली के नवीनी में आया था। पंचशील शब्द मूलतः बौद्ध साहित्य व दर्शन से जुड़ा शब्द है। चौथी-पांचवी शताब्दी के बौद्ध दार्शनिक बुद्धधोष की पुस्तक विशुद्धमाण्गो में पंचशील मतलब, पांच व्यवहार की प्रवस्तु चर्चा है। जिस पर बौद्ध उपासकों को अनुसरण करने की हिदायत दी गई है। पंचशील में शामिल सिद्धांत थे राष्ट्रवाद, मानवतावाद, स्वाधीनता, समाजिक न्याय और ईश्वरआस्था की स्वतंत्रता। इतने महत्वपूर्ण शब्द पर राजधानी की एक खास सड़क का नाम रखा जाना सुखद है। पंचशील शब्द पर सड़क का नाम रखने का सुझाव डॉ विधिवेत्ता डॉ। लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया था। नेहरू जी ने इस पर मोहर लगाई थी। डॉक्टर सिंघवी के पुत्र अभिषेक मनु सिंघवी जो काँग्रेस के नेता हैं। कूटनीति के जानकार डॉ भगवान प्रसाद सिन्हा कहते हैं कि 29 जून 1954 को तिब्बत के मसले पर भारत और चीन के बीच एक समझौता हआ।

## मोदी 3.0 की मजबूती को लेकर अलग-अलग चर्चाओं के दौर

ऋतुपण दव

मोदी मंत्रिमण्डल का गठन जरूर हो गया है लेकिन कायासों का दौर खत्म नहीं हुआ। एक बार में ही 72 सदस्यीय भारतीय भरकम मंत्रिमण्डल की बजहें लोग कुछ भी बताएं लेकिन यह नरेन्द्र मोदी की चतुराई कही जाएगी जो उन्होंने एक बारगी सारे किन्तु-परन्तु पर विराम लगा एक ती से कई विश्वासे साधे। इससे न केवल सहयोगियों बल्कि भाजपा के आत्मांगिक संगठनों को भी बड़ा संदेश दिया कि भले ही सीटें घटीं लेकिन मोदी की हैसियत वही है। घटक दलों के सहयोगियों का मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमण्डल बंटवारे में मिले पद और कदेसभी काफी भ्रमटूटा साप दिखा कि नरेन्द्र मोदी ने जो चाहा वो किया जिस साथित और धैर्य से घटक दलों के साथ पहली बैठक हुई, प्रमुख दोनों सहयोगी नीतिशाब्द और चंद्रबाबू ने मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े उससे राजनीतिक नब्ज टटोलने वालों की भी धड़कनें असहज हुईं। हम उम्र और राजनीति में मोदी से सम्मिलित होने के बावजूद नीतिशक्ति का उनके पैर छूने द्युकना सबको अब भी हैरान कर रहा है।

यह भ्रम ही साबित हुआ कि जेडीयू को रेल तो टीडीपी को सङ्केत परिवहन मंत्रालय मिलना तथ है पुरानी सरकारों में रेल मंत्रालय प्रायः गठबन्धन के सहयोगियों के खाते में रहा मौजूदा मंत्रिमण्डल में 33 नए चेहरे हैं जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पहली बार मंत्री बनने वालों में 7 सहयोगी दलों से हैं। 17 महिलाएं

A photograph of Prime Minister Narendra Modi speaking at a G7 meeting. He is wearing his signature orange kurta-pajama and glasses, gesturing with his right hand. In the background, the flags of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States are visible, along with a large gold-colored 'G7' logo.

लाडोराशप पर निशाना साधा। हालाकि इस पर सफाई भी आई। लेकिन यह भी सही है कि इस बार संघ वैसा सक्रिय नहीं दिखा जैसे पहले के चुनावों में दिखता था वहीं प्रधानमंत्री का एनडीए का 400 पार और भाजपा खुद 370 जीतने का नारा लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया। अब सबकी निगाहें लोकसभा अध्यक्ष पर हैं। जिस पर फिर कथासों का दौर शुरू हो गया है।

निश्चित रूप से विविधताओं से भरे भारत देश और उसकी राजनीति में मतांतर नए नहीं है। इसीलिए कभी लगता है कि मोदी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बेहद मजबूत है तो कभी लगता है कि भाजपा और उसके अपने महत्वपूर्ण आनुषांगिक दल ही क्यों रुक्खा हैं।

। इसपर रना होगा । ठिकरांग राष्ट्र ध्यान देने के लिए अपर से शांति नार भी बन जो हुआ ? या हुआ ? गया । ऐसे को विरोधी जरूरी है । रखा गया खत्म नहीं प्रमुख नड़ा है जिसमें अपने पैरों पर आने के बड़े दल हो क्या कहा । आंध्र प्रदेश विधानसभा में गजबका प्रदर्शन करते हुए टीडीपी-भाजपा गठबंधन में बड़े बहुमत वाली जीत हासिल की । दोनों का एजेंटा सबको पता है । टीडीपी मुस्लिम आरक्षण, परिसीमन, सी.ए.ए., अमरावती के विकास और विशेष दर्जे पर तबज्जो चाहेगी तो कमवेश जेडीयू भी बिहार में ऐसे ही एजेंटे के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव में जाएगी । महाराष्ट्र में तो अभी चुनाव होने हैं । इन हालातों में महत्वपूर्ण घटक कब तक भाजपा के हमराह रहेंगे ? जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित बिहार में पद और कद पर कई बातें होनी शुरू हो गई हैं । अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम भाजपा नीत गठबंधन सरकार को राजस्थान, पंजाब और दक्षिण के युनाइटेड परिषमों के मायने पर भी जानकारों के राय बंटी हो सकती है । लेकिन यह सच है कि असल परीक्षा के लिए लोकसभा के नियमित सत्र और नए अध्यक्ष तक इंतजार करना ही होगा । नई परिस्थितियों में खुद की छवि को बजाए मसीहाई दिखाने के बड़ी सहजत और विनप्रता से लबरेज दिखाकर र्भा प्रधानमंत्री मोदी नई एनडीए सरकार के वैसे ही सख्त मुख्यादिख रहे हैं जैसे बीते दोनों कार्यकाल में रहे लोग तब और अब भी फर्क भले हूँदे लेकिन यह कब दिखाया कोई नहीं जानता । फिलाहाल 30 जून का इंतजार है जब मन की बात के जरिए तीसरे कार्यकाल में नरेन्द्र मोदी का पहला संबोधन क्या होगा ?



# बिजली कटौती को लेकर पूर्व विधायक ने विद्युत विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, सौंपा मांगपत्र

उज्ज्वल दुनिया संवाददाता

**तिसरी संवाददाता :** इस भीषण गर्मी में धनवार विधानसभा क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक ने क्षेत्र के तिसरी, गांव व राजधनवार में पूर्व में आपूर्ति किए जा रहे 11 मेगावाट बिजली के जगह पर मात्र 4 मेगावाट बिजली सप्लाई देने समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को विद्युत विभाग को मांगपत्र सौंपा है। साथ ही अट्टीमेटम देते हुए अनिश्चितानन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।

4 सूर्योदायों को लेकर 24



जून तक का अल्टीमेटम

श्री यादव ने मुन्ना राणा, मुन्ना गुप्ता, छेंटू यादव, राजेश यादव आदि कायरक्टर्टिंगों के साथ तिसरी

विद्युत सब स्टेशन के कर्मचारी के हाथों झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड के महाप्रबंधक के नाम मांगपत्र सौंपते हुए धनवार, गांवा

गढ़वाल प्रिड को चालू करने और तमाम गांवों में जले हुए ट्रांसफर्मर और जर्जर हुए तारों को 24 जून तक बदलने की मांग की है। अन्यथा 24 जून के बाद विद्युत सबस्टेशन का घेराव करने और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की तोतावनी भी दी है।

मौके पर श्री यादव ने कहा कि 139 करों की लागत से बना पावर प्रिड बन विभाग द्वारा एनओसी नहीं देने के कारण अब तक चालू नहीं किया है। इस मामले को लेकर उन्होंने उपायुक्त को भी जानकरी दी है। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन और विद्युत सभा महाप्रबंधक ने इसका समाधान नहीं निकला तो 24 जून से विद्युत सब स्टेशन में अनिश्चितकालीन धरना भूल जाते हैं।

यदि वे गंभीर रहते तो आज इन समस्याओं का सामाना न करना पड़ता। कहा कि भाकपा माले साल के 365 दिन जनता के सवालों को लेकर लड़ाई लड़ेगी।

## उच्च न्यायालय, झारखंड के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे राजस्व अधिकारी

**गिरिडीह अमित सहाय :** रेजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करने हेतु किसी प्रकार का आदेश निर्देश मिलने से इकार किए जाने संबंधी अंचल अधिकारी बैंगाबाद का बयान अखबार में सोमवार को छपने के बाद मंगलवार को किसान जनता पार्टी के संस्थान कर्मचारी बैंगाबाद में हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमिटी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5925/2022 में 27 फरवरी 2024 को झारखंड सरकार, उपायुक्त गिरिडीह को निर्देश इकार करना समझा से परे है।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से



अलग अलग तिथियों को सात बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का प्रति तथा उपायुक्त कायालय से निर्वाचित पत्र की प्रति अंचल अधिकारी बैंगाबाद को भेज चुका हूं। उसके बाद भी अंचल अधिकारी महोदय द्वारा आदेश मिलने से इकार करना समझा से परे है।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।

आदेश का एक एक रिसीविंग एसपी कायालय के कर्मचारियों ने रिसीविंग किसानों से रुपैया जमा लेकर नहीं दी गई।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का नि�र्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का नि�र्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।

तिसरी में 32 मौजा के किसानों ने अलग अलग आवेदन करने के चार सालों के अंदर रजिस्टर टू का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। मैं स्वयं भी निर्वाचित डाक के माध्यम से

रजिस्टर टू मांगने पर अंचल अधिकारी द्वारा अवेदकों के साथ गाली गलाई करते हैं। थाना जाने पर थाना प्रभारी कहते हैं मैं अंचल अधिकारी पर केस नहीं कर सकता। बैठक में तिसरी अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु एसपी को सभी पीड़ित किसान ने अलग अलग आवेदन देने का निर्वाचन।



